बुराई की उम्र बड़ी छोटी होती है।
– अज्ञात

सीमा पर कायम तनाव

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को फोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि सीमा पर सैनिकों को अलग करने और तनातनी कम करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी करना दोनों देशों के हित में है।

मोहन सिंह।

पिछले महीने की 15 तारीख को हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारत–चीन सीमा पर कायम तनाव में कमी आने के ठोस संकेत पहली बार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को फोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि सीमा पर सैनिकों को अलग करने और तनातनी कम करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी करना दोनों देशों के हित में है।

इसके बाद यह खबर आई कि दोनों देशों के सैनिक अपने–अपने स्थान से कुछ पीछे हटने शुरू हुए हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के ब्यौरे अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई खबरों में एकसूत्रता का अभाव है। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में सीमा पर 3 किलोमीटर का बफर जोन बनाने पर सहमति हुई है। यानी दोनों देशों की सेनाएं डेढ़–डेढ़ किलोमीटर पीछे हटेंगी और बीच के तीन किलोमीटर खाली इलाके में कोई हरकत करने से पहले उन्हें दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी देनी होगी।

खबरों में यह स्पष्ट नहीं है कि डेढ़ किलोमीटर पीछे हटना वे कहां से शुरू करेंगी– दोनों सेनाओं की मौजूदा स्थिति से, या ताजा विवाद शुरू होने के पहले अप्रैल में दोनों सेनाओं की जो स्थिति थी, वहां से? यह भी समझना बाकी है कि यह विश्वास बहाली के मकसद से उठाया जा रहा एक तात्कालिक कदम भर है, या इसे देर तक कायम रखने का इरादा है। एक महत्वपूर्ण सवाल भारतीय सीमा के अंदर चल रहे निर्माण कार्यों का भी है। बफर जोन बनाने के लिए भारतीय सेना अपनी मौजूदा स्थिति से डेढ़ किलोमीटर पीछे हटती है, तो क्या उसकी जद में ये प्रॉजेक्ट भी आएंगे? जाहिर है इस इलाके में सड़कों और पुलों का निर्माण भारत के दूरगामी राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है और इनका किसी वजह से अटकना देश के लिए रणनीतिक नुकसान साबित होगा।

बहरहाल, भारत–चीन सीमा पर शांति की जरूरत से किसी भी स्थिति में इनकार नहीं किया जा सकता। यह अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार करते हुए शांति की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। सीमा पर न्यूनतम समझ कायम करने के बाद बातचीत के जरिए आपसी विवाद सुलझाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। हिंसक झड़प की घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल के बीच भी भारत ने अलग–अलग तरीकों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि अपनी एक–एक इंच जमीन को लेकर वह पूरी तरह सजग है। इसलिए चीन को या किसी को भी इस मामले में कोई गफलत नहीं पालनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर भारत और चीन हमेशा एक–दूसरे के पड़ोसी ही रहेंगे। लड़ाई दोनों को विकास की दौड़ में बहुत पीछे धकेल देगी, जबकि आपसी दोस्ती के जरिये वे अब भी इक्कीसवीं सदी को एशिया की सदी बना सकते हैं।

सहजीवी सद्भाव

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

शीओ बेंक्यो क्योसे से अपना शोध लेख विकसित कर सकते थे जिसमें बौद्ध धर्म के मौलिक मूल्यों जैसे करूणा या सार्वभौमिक दया का आह्वान किया गया हो, इसके साथ ही महायन शोध लेख जिसमें यदि सभी प्राणीशूद्र या अपर्याप्त हैं तो किसी अन्य की तुलना में अपनी भलाई देखने का कोई कारण ही नहीं बनताय या एक और महायन विचार है जिसमें सभी जीव अमिदा(अमिताभ) बुद्ध होने को सांझा करते हैं। लेकिन बेंक्यो का मुख्य रूझान यह था कि समाज में एक साथ रहा जाए, जिसे धर्म के चश्मे से देखने पर, वह अन्योन्याश्रय अभ्यास सिद्धांत से परे जाकर व्यवहार में लाया जा सके, इसलिए उनके द्वारा किसी भी विस्तृत दार्शनिक सिद्धांत को विकसित करने की कोशिश प्रतीत नहीं होती है।

संपादकीय

52 राष्ट्रों का समर्थन

नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, जिसे लेकर इतना बावेला मचा है, चार कुकर्मों से दूर रहने की सलाह दी गई है– अलगाववाद, तख्तापलट, आतंकवाद और विदेशी ताकतों से गठजोड़। कोई भी देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है और हाल में हुई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चीन को 52 राष्ट्रों का समर्थन भी मिला है। लेकिन चीन को हांगकांग तथा अन्य 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों' को अधिक स्वायत्तता देनी होगी और वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना होगा। रास्ता यही है कि हांगकांग वासियों को विलय के समय निर्धारित 'एक देश दो व्यवस्था' की शर्त का पूरा लाभ मिले। अमेरिका इन खबरों से चिंतित है कि कहीं दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नंबर एक न हो जाए। इसलिए वह हांगकांग को बेस बनाकर चीन में तख्तापलट की फिराक में है। हांगकांग में कुछ महीनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखें तो इनमें अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ साफ दिखाई देता है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल एयरपोर्ट बंद कर दिया और संसद नहीं चलने दी, बल्कि उसकी इमारत पर अमेरिका और ब्रिटेन के झंडे फहराए और उनके राष्ट्रगान गाए। गार्जियन (लंदन) के अनुसार इन विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए लोगों में पुलिस वालों की संख्या प्रदर्शनकारियों से कहीं अधिक थी। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो तख्तियां दिखाई देती हैं, उन पर लिखा होता है 'फ्री हांगकांग'। जिस हांगकांग के लिए चीन ने 100 साल इंतजार किया, उसे वह खुद से अलग कैसे होने देगा? चीन उन्हें डंडे के बल पर अपने साथ नहीं रख सकता लिहाजा क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर उसे अड़ियलपना छोड़ना होगा।

19वीं शताब्दी के शुरू में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जे के अलावा चीन से आने वाली चाय के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी संपूर्ण एकाधिकार था।

99 साल की लीज

अजेय कुमार।।

हांगकांग की वर्तमान उथल–पुथल को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि लगभग 150 वर्ष पहले किन परिस्थितियों में ब्रिटेन ने इसे चीन से छीना और फिर कैसे यह चीन को वापस मिला। 19वीं शताब्दी के शुरू में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जे के अलावा चीन से आने वाली चाय के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी संपूर्ण एकाधिकार था। चीन के व्यापार पर और यूरोप से सामानों की आवाजाही पर भी उसी का लगभग एकछत्र नियंत्रण था। नमक, अफीम, पान का पत्ता और कुछ ऐसी ही चीजों के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने बेइंतहा पैसा कमाया। इसमें गवर्नर जनरल का भी हिस्सा होता था।

उस वक्त चीन में चिंग–राजवंश का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी इतने बदमाश थे कि वे चीन से चाय खरीदते थे और अपना व्यापार–घाटा कम करने के लिए उन्हें अफीम खरीदने को कहते थे। चीन ने जब इसके लिए मना किया तो ब्रिटेन ने बाकायदा युद्ध छेड़ दिया जो प्रथम अफीम युद्ध (1839–1842) के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में चीन हार गया और 29 अगस्त, 1842 को नानजिंग संधि हुई जिसमें चीन को अंग्रेजों की सभी शर्तें माननी पड़ीं।

इसमें पहली यह थी कि चीन ब्रिटेन से अफीम की खरीद जारी रखेगा। दूसरी शर्त युद्ध का सारा खर्च चीन पर थोपने की थी। यह खर्च नकद वसूलने के बजाय तय हुआ कि अपना हांगकांग नामक टापू चीन 1 जुलाई 1898 से 99 वर्षों की लीज पर ब्रिटेन को देगा। यह लीज पूरी होने के बाद 1997 में हांगकांग वापस चीन को सौंपा गया।

हांगकांग की तरह ही चीन के कई अन्य क्षेत्र जैसे मकाऊ, तिब्बत आदि भी विदेशी शक्तियों ने बल प्रयोग के जरिये उससे छीने थे। वापसी पर इन तमाम क्षेत्रों को 'विशेष प्रशासनिक क्षेत्र' का दर्जा दिया गया। अलग इतिहास के चलते इन्हें जबर्दस्ती चीन की कम्युनिस्ट व्यवस्था में लाना उचित नहीं था। 2016 की जनगणना के अनुसार हांगकांग की कुल 75 लाख आबादी का 92 प्रतिशत भाग चीनी मूल का है। रही बात डेमोक्रेसी की तो वहां वह वैसी ही है जैसी पूंजीवादी देशों में होती है। हांगकांग में खरबपतियों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, परंतु आपको वहां ऊंची मीनारों के साथ झोपड़पट्टियां भी दिख जाएंगी। रिहायश बहुत महंगी है। प्रायः लोग छोटे–छोटे पिंजड़े नुमा घरों में रहते हैं, गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की भयंकर कमी है।

जो तमाम कमियां एक पूंजीवादी देश में होती हैं, सब वहां मौजूद हैं। जो धंधे चीन में किन्हीं कारणों से नहीं हो सकते, वे सब हांगकांग में होते हैं। पार्टी के कुछ भ्रष्ट नेताओं और बड़ी–बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों को जो अंडरहैंड पेमेंट्स करनी होती हैं, वे सब यहां होती हैं। बैंकों के भ्रष्ट अधिकारी, जमीन के कारोबारी, बड़े–बड़े फ्लैट बेचने वाले निर्माण उद्योग में लगे बिजनेसमैन सब यहां हैं। इनका न केवल घरेलू खरीदारों से नाता है, बल्कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों से भी लेन–देन है। इन कंपनियों के हेडक्वार्टर हांगकांग में हैं और ये सब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एडवाइजरी कमेटियों को भी प्रभावित करते हैं।

अष्टयोग-5011

3	6		4	7	2	
	35	5	31		27	
	2			1	6	
1	33	6	32		31	2
	6		1	5	3	
4	33	3	30		35	6
7		2			1	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5010 का हल

5	7	2	4	3	6	1
3	33	1	25	6	28	2
4	6	5	3	1	2	7
1	32	6	35	4	32	4
2	1	7	4	5	6	3
7	33	3	33	7	41	6
6	3	4	1	2	7	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

खत्म करने के लिए कुछ बड़े कदम

मोहन। चीन के राष्ट्रपति ने पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही हांगकांग में जमीन–जायदाद के तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों को पकड़कर उन पर भारी जुर्माने ठोके गए हैं। भ्रष्टाचार पर शी चिनफिंग का मशहूर वाक्य है, 'केवल मच्छरों को नहीं, बाघों को पकड़ना भी जरूरी है।' उन्होंने तो पार्टी के हर नेता के दफ्तर के साइज से लेकर नेताओं के लंच या डिनर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की संख्या तक को लेकर कड़े नियम बना दिए हैं। उनके शासन में चीन ने जो आर्थिक तरक्की की है, वह पश्चिमी देशों, ,खासकर अमेरिका को बौखला देने वाली है। 'मेड इन चाइना, 2025' की योजना चीन को उन सभी आयातों से मुक्त कर देगी जिनके लिए आज वह विदेशों पर निर्भर है। 2013 से शुरू किए 'एक बेल्ट एक रोड' जैसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट से चीन 80 देशों को रेलवे, सड़क, बंदरगाह, पाइप लाइन, इत्यादि के माध्यम से आपस में जोड़ रहा है।